CHAPTER 44

POLITICAL SCIENCE

Doctoral Theses

01. अमित कुमार
ज्ञान विकास और राजनीति: स्वतंत्र भारत मे कुम्हार ।
निर्देशिका: प्रो. मधुलिका बनर्जी
Th 26868

सारांश

यह शोध कायय 'ज्ञान, विकास और राजनीति: स्वतंत्र भारत में कुम्हार" द्वारा राजनीति विज्ञान में एक नए विमशय ज्ञान की राजनीति' के संबंध में कुम्हार के ज्ञान' को समझने की कोशशश की गई है। कुम्हार के ज्ञान को भारत में आधुतनिक विकास की प्रक्रिया में समझने की कोशशश की गई है। *21*वी शताब्दी में आधुतनक विकास के दोष वह ज्ञानाधार ही है, जिसको अब तक विकास और मानवीय मुक्ति का स्रोत माना जा रहा था। यह ज्ञान प्रकृति को मानव हित के लिए के इस्तेमाल करने की प्रक्रिया में, जिस गति से प्रकृति को नष्ट कर रहा है, उससे विकास नहीं विनाश हो रहा है। इससिए अब यह सोच उबर रही है क्रक मानि समाज के पास आधुतनकिा से पहले जो ज्ञान था, जिसके सहारे इिने समय तक, बिना विनाश किए विकास हो पाया था, तया उसके कुछ अंश या नज़रिया को दोबारा समाज में आधधपत्य मिल सकता हैं, ताकि वैकल्पिक विकास की कुछ अलगधारणा बन सके*?* आधुतनक विकास के विकपपों के तौर पर पारंपररक ज्ञान की बात की जा रही है। ज्ञान के इन स्रोत को पारम्परिक न कहकर, हम इन्हें पहिे से मौजूद ज्ञान व्यिस्थाओं' *(AEKS)* के नाम से अभी पहचानने की कोशशश ताकि उनकी पारंपररकिा से ज़्यादा उनकी प्रासंधगकिा पर ज़ोर हदया जाए। और यह ज्ञान विकास के विकपप के तौर पर देखा जाता है। यहा *AEKS,* आधुतनक विकास व्यिस्था के प्रभुत्ति के पीछे यहा पाँच स्थनों – ऐतिहाशसक, राजनीतिक अथयव्यिस्था की बाजारिादी व्यिस्था, नीति-निर्मण, सामूहीक कार्यवाही और ज्ञानमीमांसा को अपने मूल प्रश्न के रूप से देखिता है। इस शोध में, मैंने ज्ञान, विकास और राजनीति के मध्य कुम्हार के ज्ञान को रखकर इनमें आपसी सह-संबंधों की पहचान करने का प्रयास क्रकया हैं। कुम्हार का ज्ञान एक पारंपररक ज्ञान के रूप में है, जजसका आशय आधुतनक विकास के ज्ञान से अिग वैकल्पिक विकास के पारंपररक ज्ञान से है, यहा वैकल्पिक ज्ञान की राजनीति एक अहम भूमिका में रहेगी।

विषय सूची

1. भूमिका 2. ज्ञान की राजनीति 3. कुम्हार का ज्ञान 4. नागरिक समाज और कुम्हार 5. भारतीय राज्य बाजार और कुम्हार 6. निष्कर्ष. संदर्भ ग्रंथ सूची. परिशिष्ठ।

02. ANANT PRAKASH
Analyzing Bicameralism in Parliamentary Federations: Comparative Study of Germany and India.
Supervisor: Prof. Sangit Kumar Ragi
Th 27261

Abstract

The central problematique that my research dwells upon relates to the raison d`etre of the bicameral legislature and its status and role in the parliamentary federations. To decode the different dimensions of the problematique, I will rely on the comparative study of bicameralism in Germany and India. The increasing relevance

of the bicameral legislature and its impact on the federal pattern of governance create a combination of strong hypotheses and scope for reckoning and analysis. This study would help in understanding the relevance of a bicameral legislature in enhancing regional representation and accommodating regional aspirations in multiethnic, multinational, multicultural, plural, or divided societies or countries. This study may also provide insights into the efficacy of bicameralism in promoting democratic governance and policymaking in various contexts. Additionally, the study can identify the factors that contribute to the success or failure of bicameral systems and provide recommendations for enhancing the functionality of bicameral systems in federal nations.

Contents

1. Introduction 2. Bicameralism in federations: theoretical outlook 3. Bicameralism in Germany: political institutions, processe, and outvomes 4. Bicameralism in India: political institutions, processe, and outvomes 5. Comparative analysis of bicameralism in Germany and India: Critical issues 6. Conclusion. Bibliography. Annexure.

03. भावना

सामुदायिक हिंसा एवं जेंडर : मुजफ्फरनगर हिंसा के संदर्भ मे केस अध्ययन।

निर्देशिका: प्रो. संगीत कुमार रागी

Th 27262

सारांश

सार प्रस्तुत शोध ग्रन्थ का विषय 'सामुदायिक हिंसा एवं जेंडर: मुज़फ्फरनगर हिंसा के सन्दर्भ में केस अध्ययन' है। यह सामुदायिक हिंसा एवं जेंडर के अंतर्क्रियात्मक सम्बन्ध पर आधारित है जो हिंसा की अवधारणात्मक विकास की समझ को विकसित करता है। सामुदायिक हिंसा भारत में सर्वाधिक चर्चा का मुद्दा रहा है भारत में सामुदायिक हिंसा कि घटना देश में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। सामुदायिक अशांति के इतिहास पर एक सरसरी नज़र डालने से पता चलता है कि भारत में विभिन्न समुदायों के बीच हिंसक संघर्ष जैसे मुसलमानों और हिन्दुओं के बीच; ईसाई और हिन्दू; सिख और मुसलमान; सिख और हिन्दू और कभी-कभी दलितों और उच्च वर्ग के हिन्दुओं के बीच। भारत में अल्पसंख्यक समूहों को प्रभावी प्रवचनों और वास्तविक और कथित मतभेदों के प्रतिनिधित्व के माध्यम से लक्षित और हाशिए पर रखा गया है जिसमें जातीय आधारित भिन्नता, लिंग और जाति-आधारित मतभेद आदि शमिल हैं। इन मतभेदों को हीन और असामान्य के रूप में देखा जाता है। सामुदायिक हिंसा ने सदैव पीड़ित समुदाय विशेषकर महिलाओं को सरल लक्ष्य के रूप में देखा है। अत: प्रस्तुत शोध के माध्यम से सामुदायिक हिंसा के कारण पीड़ित महिलाओं के अनुभव को जानने का प्रयास किया गया है। जिसका मुख्य प्रश्न यह है कि यदि महिलाओं को सदैव 'सम्मान का प्रतीक' माना जाता है तो सामुदायिक हिंसा के दौरान इसी प्रतीक को युद्ध के हथियार के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? एवं महिलाओं को ही क्यों एक 'सरल लक्ष्य' के रूप में देखा जाता रहा है? पूरे विश्लेषण और चर्चा के आधार पर इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मुज़फ्फरनगर में हिंसा के केंद्र में महिलाएं रही है। शुरुआत में इसे 'दुश्मन समुदाय' के विरुद्ध संघर्ष में, सम्मान के नाम पर जायज़ ठहराया गया है।

विषय सूची

1. प्रस्तावना 2. भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामुदायिक हिंसा की संकल्पना 3. हिंसा एवं महिलाएं: एक सैद्धांतिक अवधारणा का अवबोधन 4. मुजफ्फरनगर एक हिंसा, 2013 5. परिणाम, चर्चा एवं सुझाव 6. संदर्भ ग्रंथ सूची . परिशिष्ठ।

04. JYOTI BHARTI

Gender Equality and Cultural Rights in India: An Analysis of the indian state practices in the aftermath shah bano judgment.
Supervisor: Dr. Nasreen Chowdhory
Th 26869

Abstract

The research aims to examine a better alternative to trace women's rights in minority communities. Muslim women's rights are being politicized for so long but the issue has not been resolved. In this context, I would like to examine how the two terms, gender equality, and cultural diversity are accommodated in the post-colonical indian state. The research tride to examine the problem with the lens of co-existing gender rights and religious rights. In the surrounding noisy environment of religious tension and gender rights of of muslim women, some state and non-state actors are facing the challenge of realizing the right approach. The muslim women (protection of rights on divorce) act, 1986 intenrionally was not designed for the democratic rights of mislim women. The high courts' judgment shows that the maintenance of divorced condified Islamic law in 1986prevented muslim women more effectively than secular state law. Cultural diversity in india pertains to religious diversity, caste, religion, and ethnicity. The research examinded the dilemma of accommodating gender equality with religious freedom, wherein the role of the indian judiciary and how the state maintains a balance between the demands of religion and gender justice in delivering judgments and enacting laws on maintenance and divorce rights.

Contents

1. Introduction 2. A conceptual exploration: "Equality" in gendered and cultural "rights" 3. Historical exploration: muslim women, personal laws, and challenge of democracy 4. A filed work analysis: muslim women's opinions and laws and cultural governing bodies 5. Muslim women's rights as multicultural claim 6. Conclusion 7. Annexure 8. Bibliography.

05. काजल
भारतीय दलीय व्यवस्था एवं राष्ट्रीय राजनीति मे क्षेत्रीय दलों की भूमिका: संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन तथा राष्ट्रीय जंतांत्रिक गठबंधन का तुलनात्मक अध्ययन।
निर्देशिका: डा. अनीता टैगोर
Th 27146

सारांश

राजनीतिक दल तकसी भी देश की राजनीति और सार्वजतनक जीर्न का अतभन्न अंग है। ई तकसी देश के शासन में कई महत्र्पूर्व और आर्श्यक कायव करि हैं। राजनीतिक दल जनि और सरकारों के बीच मध्यस्थ का काम करि हैं। राजनीतिक दलों को संघ, समहू और संस्थाओ के रूप में भी पररभाति किया जाता है जिनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है सत्ता की प्राति। राजनीतिक दलों के तर्तभन्न आधार होता हैं तजस पर दल का गठन आधाररि होता है, जो निम्नतलति है: पहला, तर्चारधारा पर आधाररि दल, सामातजक, आतथवक एर्ं सांस्कृतिक तर्चारधारा दलों के सदस्यों को आपस में जोड़ी हैं। उदाहरर्णत भारि में 1977 में गतठि जनि पार्टी के सदस्यों को आपस में जोड़ने वार्ली गांधीवार्दी विचारधारा ही थी। दूसरा, हितों पर आधारीत दल, दल तर्तश तहिों का प्रतितनतधत्र् कर सकि हैं। यह तहि बहुत प्रबल हो सकि है अथावि् जाति आधाररि तहि- भारि में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी), समाजवार्दी पार्टी (एसपी) और राष्ट्रीय लोक दल (आरजेडी)। साथ ही साथ गर्व आधाररि तहि - कम्युतनस्ट पार्टी ऑफ़ इंतडया (भाकपा), कम्युतनस्ट पार्टी ऑफ़ इंतडया मात्सवस्ट (भाकपा(एम)) र् समुदाय आधाररि तहि – ऑल इंतडया मजतलस-ए-इत्तेहादुल मुतस्लमीन (एमआईएम), क्षेत्रीय तहि अतिल भारीय अन्ना द्रतड़ मुनेत्र

कज़गम (एआईएद्रमुक), द्रतई मुनेत्र कज़गम (द्रमुक) और तिसरा, विषय पर आधाररि दल, जब कुछ विशेष विषय सामातजक और राजनीतिक पर्टल पर उभरि हैं, उदाहरण 1977 में जनि पार्टी एरं 2012 अन्ना हज़ारे के भ्रटाचार तमर्टाओ आंदोलन के पश्चाि आम आदमी पार्टी (आप) का गठन। हीं चौथे दल व्यति आधाररि होते हैं, जहा व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए विचारधारा , हित एरं विशेष प्रयोग तकए जाते हैं। उदाहरर् लोक जनशति पार्टी जो राम तर्लास पासर्ान के आस-पास ही सीतमि है। ई तजन आदशों को आगे बढ़ाना चाहि है, उसके अनुयायी तबना सोचे-समझे उसी सांचे में डालि जाते हैं, क्योंकी दल में प्रत्येक व्यति न विचारशीलहोती है और न उसमे तार्किक बुद्धि होती है।

विषय सूची

1. परिचय 2. भारतीय दलित व्यवस्था एवं क्षेत्रीय दल: उदय व उत्थान 3. भारत मे गठबंधन राजनीति एवं क्षेत्रीय दल: प्रसार एवं प्रभुत्व 4. क्षेत्रीय दल एवं राष्ट्रीय जंनतांत्रिक गठबंधन 5. क्षेत्रीय दल एवं सयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 6. समसामयिक भारतीय राजनीति एवं क्षेत्रीय दल: परिवर्तनीयता व प्रासंगिकता निष्कर्षत्मक अवलोकन परिशिष्ठ संदर्भ- स्रोत

06. KUNDAN KUMAR
Global Climate Change Negotiation: A Comparative Study of Role of China and United States of American in Copenhagen and Paris Summits.
Supervisors: Prof. Navnita Chadha Behera and Dr. Rityusha Mani Tiwary
Th 26870

Abstract

Global political dynamic always played a significant role between the nations who Participated in the conference of parties organized under UNFCCC. The research originaly conceptualzed in this thesis had sought to understand a boader puzzle, that was titled as 'peace ecology and climate change: A comparative study of Copenhagen and paris summits' it had sought to analyze laws and policies as mechanisms deployed the conference of the parties (COPs) under the UNFCCC in order to mitigate and prevent the asverse impacts of anthropogenically induced climate changes. Specifically, the thesis had selected the Copenhagen and paris summits for a comparative analysis. Studying the dynamic and provisions of the global climate change negotiations ad various summits helped the author understand their strengths and linitations. While the initial hypothesis of this study was that cooperation in climate change summits does not necessatily reflect the intention of the parties in ddressing the ussue, further research and its impact have served as important rationales for cooperation at these summits. So, before discussing the main findings of this study, it is important to briefly explain som other aspects of the research journey which gradually brought about subtle yet significant transformations in the conceptualization of the study itself.

Contents

1. Introduction 2. Peace ecology: A conceptual framework 3. Global climate change negotiations: an overview 4. China's climate change policy: domestic imperatives and global commitments 5. Climate change policy of the US: domestic exigencies and global engagements 6. From competition and cooperation: explaining the journey from the Copenhagen to the Paris summit. Conclusion and Bibliography.

07. नरेश कुमार
Popular Religiosity and the Politics of Margins: A Study of Kanwar Pilgrims.
निर्देशिका: प्रो. मधुलिका बनर्जी
Th 26871

सारांश

पिछले चार दशकों के दौरान उत्तर भारत में कावड़ की यात्रा एक व्यापक धार्मिक परिघटन के रूप में उभरी है इन वर्षों में वह एक संगधटित एयर नियोजित और समूहिक घटना बन गई है कुछ प्रेक्षक इसे हिन्दू धर्म में समरूपी की बढ़ती प्रवृत्ति का उदाहरण मानते है तो कुछ इसे हिदूतत्व की सांस्कृतिक राजनीति से जोड़ कर देखते हैं कावड़ की यात्रा से संबन्धित अधिकांश अध्ययनों से सांस्कृतिक मानवशास्त्र का दृष्टिकोण ज्यादा प्रबल रहा है लेकिन प्रस्तुत शोध में हमने इस परिघटन के राजनीतिक निहितार्थों को समझने की चेष्टा की है हमारा शोध इस जिज्ञशा से निर्देशित है की जब एक सांस्कृतिक धार्मिक अभिव्यक्ति इतनी विशाल जन – पृघटना बन जाती है तो वह राजनीतिक गतिविधियों और प्रक्रियाओं किस प्रकार प्रभावित करता है इस लिए हमारे शोध का केंद्रीय प्रश्न इसी बिन्दु से उभरता है की कावड़ की धार्मिकता स्थानीय राजनीतिक गतिविधियों और प्रक्रियाओं किस प्रकार प्रभावित करता है हमारा यह शोध दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर केन्द्रित है अत हमने इस प्रश्न को इस सीमित क्षेत्र मे रख के देखने का प्रयास किया है लेकिन इस क्षेत्र पर केन्द्रित रहते हुये हम इस तथ्य के प्रति सचेत हैं की यह इलाका उत्तर और पूर्वी भारत से पिच्छले चार दशकों में आए परवासी लोगों का स्थल है कथित तौर पर मध्यवर्गीय दायरों में कावड़ की यह यात्रा कम पढे लिखे , देहाती या अर्धशहरी लोगों की धार्मिकता मनी जाती है रोहमर्रा के विमर्श में यह धारणा रूढ होती गयी है की कावड़ पंद्रह बीश दिनों के लिए शहर पर दावेदारी करने का प्रकितात्मक अनुष्ठान है दूसरे शब्दों में कहें तो समाज के जिन वर्गों और समूहों को सत्ता की स्थायी संरचना में उनकी जायज जगह न मिलती, वो उसे इस यात्रा के माध्यम से चंद दिनों के लिए हंसिल कर लेना चाहते है इसलिए हमारा केंद्रीय प्रश्न थोड़ा और आगे जाना चाहता है जहां हम यह पढ़ताल करने की कोशिश करते है की कावड़ की परिघटना को हम आधुनिक शिक्षित मध्यवर्गीय मानसिकता व्नाम गैर आधुनिक मानसिकता के द्वंद के रूप में भी देखा जा सकता है ।

विषय सूची

1.हिन्दू धर्म: लोकधार्मिकता का समरूपीकरण 3. शहर का सीमांत, सीमांत की सत्ता और कांवड 4. कांवड: प्रबंधन, नीतियाँ तथा राजकीय संरक्षण 5. जनसमूहों की गतिकी व जनाधारित-राजनीति. निष्कर्ष.. परिशिष्ठ .संदर्भ ग्रंथ सूची

08. P. ARUN

Communications Survillance in Democracy: A Comparative Study of India, United States of America and United Kingdom.

Supervisor: Prof. Ujjwal Kumar Singh

Th 27145

Abstract

This study investigates the emergence of communications surveillance, specifically on telegraph and telephone communications in three liberal democracies – United States, United Kingdom and India. Communications technology is neither an abstract nor neutral and monolithic entity; instead, it is driven by the complex interplay of forces, where technology intersects with law and politics. The research explored how telegraph and telephone communication surveillance evolved in the nineteenth and twentieth centuries. It carries out a comparative study of the developments in the legal regimes and surveillance practices in two western democracies and then mainly focuses on Indian democracy during the colonial and postcolonial eras. For this, it looks into different purposes and reasons of the state to understand why it requires exemptions for surveillance. Were there any constitutional limitations or legal restraints on communications surveillance? How did it affect the nature and scope of rights and freedoms? How did the unenumerated right to communication privacy, without any explicit mention in the constitution, go on to become a major claim in liberal democracies? What circumstances and factors which caused the pursuit of the right to communication privacy? The theoretical frame this study engages with is liberal democracy; whereas

the idea of exception is explored from the concepts of the "reasons of the state" (Friedrich) and the "state of exception" (Schmitt and Agamben) to explain the dilemmas of liberal democracy. First, this research demonstrates the features of the executive oversight model and the reason behind its abandonment in two western liberal democracies, in contrast to its continued presence in India even today. Second, surveillance practices in colonial India have not been deeply researched and explored; therefore, this research attempts to fill this gap in the existing knowledge on communications surveillance. Lastly, this research contributes to understanding the significance of trust over surveillance in a democratic system, following which the individuals can exercise their freedom to communicate their heart and mind.

Contents

1. Introduction 2. Monitoring dots and dashes: telegraph surveillance in Britain and America 3. "We are at war": stranglehold and communications surveillance during wartime and interwar period 4. "The uninvited and omnipresent ear" : telephone surveillance in Britain and America 5. "Everywhere are spread the telegraph wires" : telegraph and surveillance law in colonial India 6. The difficulty of being in touch: telegraph surveillance in colonial India 7. Neither disturbed nor modified: communications surveillance in post- colonial India 8. Communications surveillace under organized crime laws and anti-terror law in India. Conclusion. Bibliography. Appendix.

09. ROY (Anubhav)

Study of Socialist Indian's Reception of the U.S.' Soft Power Exports,1966-71.

Supervisor: Prof. Sanjeev Kumar H.M.

Th 26872

Abstract

The years between 1966 and 1971, which encapsulated Indira Gandhi's maiden tenure as Prime Minister, India experienced significant transformations, both domestically and internationally. At home, following the backlash against her initial campaign to warm up to the US in 1966, Indira Gandhi's government began deepening India's adherence towards socialist ideals and policies, empowering the state through moves like expanded nationalisations and bold amendments to the constitution. Alongside, externally, with New Delhi's distrust for the US soaring due to disputes over the Vietnam War, the American military bias for Pakistan, and Washington's slowing food supplies to India, her government expedited its turn to the Soviet Union for strategic and military support amidst the Cold War. Meanwhile, India contrastingly continued to sustain a noticeably strong preference for several material and ideational, economic and cultural inputs from the US, ranging from Ford Foundation grants and Fulbright scholarships to Coca-Cola's beverages and Chevrolet's sedans. A primary purpose of this thesis is to chronicle in detail the extent of this contradiction between India's acceptance for attractive American inflows and influences despite its state's growing socialist convictions and partnerships during this intriguing period. From the conceptual stand-point, the narrative so derived is then weighed against the core arguments and tenets of the still widening discourse soft power, a notion that is essentially an extension of the broader neo-liberal proposition of mitigating conflict in international relations through complex interdependence. A large part of the research for this thesis relies on the conventional historical method, based upon the assessment of archival data extracted from multiple primary sources, ranging from government correspondences to newspaper reports. To enhance the narrative and paint a holistic picture of the period under study, an array of Bollywood films and articles of a leading American

magazine from the era are also subjected to content analysis. While the thesis spans seven chapters in all, its five core chapters are an evaluative account of the roots of India's rising disagreement with the US in the mid-1960s; subsequent entrenchment of socialist policies; simultaneous military partnering of Moscow; contrasting acceptance of financial and technical support from non-state American actors; and sustained affinity for softer American exports such as magazines, beverages, and cars.

Contents

1. Introduction 2. The roots of the India-US trust deficit in the mid -1960s 3. The deepening of India's socialism and convergences with the Soviet Union 4. The hostility for-state-led American presence in India 5.The US' financial, intellectual, and technological support to India 6. The overwhelming Indian demand for certain icons of American consumerism 7. Conclusion. Appendix. Bibliography

10. सन्रि

दिल्ली विशविदयालय मे विधा –वाचस्पति (राजनीति विज्ञान) उपाधि हेतु शोध- प्रबंधन.

निर्देशिका: प्रो. रवि रंजन

Th 26876

सारांश

इस शोध का उद्देश्य लैंगिक असमानताओं के कारण उत्पन्न हुई सामाजिक समस्याओं को समझते हुए एक "लैंगिक संवेदनशील" और "लैंगिक भेदभाव विहीन" समाज बनाने हेतु राज्य के द्वारा बनाई नीतिओं का विश्लेषण करना है। इस शोध में इस बात को समझने का प्रयास किया जाएगा कि, किस प्रकार से "संरक्षणात्मक नीतियाँ" और "महिला सशक्तिकरण" से जुड़ी राज्य की योजनाओं का अध्ययन किया जा सके जिससे "पुत्रीत्व)Daughterhood)" और राज्य के बीच के संबंधों को समझना आसान हो जाए। बेटिओं की स्थिति को बेटों की तुलना के समतुल्य बनाने के लिए बहुत से नीतिगत कार्यक्रमों के द्वारा भारतीय राज्य और उसकी संस्थाएँ लोकतांत्रिक पहल करती रहीं है, परंतु बेटिओं की सामाजिक स्थिति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नही आया है, उल्टा शिशु लिंगानुपात लगातार कम होता जा रहा है। इसी समस्या को ध्यान में रखकर उत्तर वेश्वीकरण के दौर में सरकार नें प्रतिउत्तर में बहुत सी योजनाएँ आरंभ की हैं और शिशु लिंगानुपात की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न राज्यों में इन योजनाओं को संचालित भी किया गया है। लेकिन अब सवाल उठता है की, क्या केवल नीतिओं के स्तर पर ही बदलाव करके और अभियान चलकर लैंगिक संबंधित विषमता को ख़त्म या कम किया जा सकता है इसीलिए आवश्यक है की सुरक्षात्मक नीतिओं और सशक्तिकरण के वादविवाद को समझते हुए राज्य - और नागरिकों के सम्बंधों को पुत्रीत्व के दृष्टिकोण से समझा जाए। यह शोध इस तथ्य का अन्वेषण करेगा की किस प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जेसे केंद्रीय कार्यक्रमों के शुरुआती परिणामों के अनुसार हरियाणा जैसे कम लिंगानुपात वाले राज्य के लोगों की सोच एवं समझदारी में पिछले कुछ वर्षों में बदलाव आया है या नही? और क्या हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार बालिका शिशु की संख्या में बढ़ोतरी को इस योजना की सफलता के रूप में देखा जा सकता है? तथा जनसंख्या के गुणात्मक बदलाव एवं पुत्रीत्व)Daughterhood) के सैद्धांतिक पक्ष को इन नीति के माध्यम और बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है?

विषय सूची

1. परिचय विवरण 2. भारत मे राज्य पुत्रित्व संबंधों का सिद्धांतों का परिपेक्ष्य 3. 1990 के बाद से महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली सुरक्षात्मक नीतिया और शाशक्तिकरण की सरकारी योजनाओ के प्रभावों का अध्ययन 4. जन्म के समय शीशु लिंगानुपात मे असंतुलन का आकलन : भारत के हरियाणा राज्य के संदर्भ मे "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ "के राष्ट्रीय कार्यक्रम का मध्य अवधि के प्रभाव का अध्ययन 5. शीशु लिंगानुपात के संदर्भ मे सरकारी नीतियों के प्रभवों का आकलन : गुरुग्राम जिले के गाँव गढ़ी हरसरु और मेवात जिले के गाँवसुनारी का सर्वेक्षण 6. संतुलित लिंगानुपात ही शाशक्तिकरण का स्रोत : समस्या सुझाव एवं निष्कर्ष.संदर्भ ग्रंथ सूची. परिशिष्ट।

11. SANTOSH KUMAR

Global Poverty and the Politics of Redistribution: Innovating an Institutional Framework.

Supervisor: Prof. Ashok Acharya

Th 26873

Abstract

Globle poverty is one of the real mormal problems of our time faced by humanity, especially in the global south. The western moral consmopolitans like Thomas pogge, simon caney, Elizabeth ashford, Pablo gilabert ctc. Understands it as violation of socio-economic human rights but pogge also discuss it as a harm the well-off the developed national inflict on the global poor, especially powerless people of global south. Regarding the duty they have a consensus but propose it differently like pogge prescribes negative duty of justice only while caney and others prescribe positive duties too. For many of them positive duty is either over-demanding or supererogatory and they get back to the instirutional reforms at the global level while caney proposes an egalitarian instirutional reform at the global level to address acute poverty. Cosmopolitans like gilabert and peter singer also provide consent to this proposal however, both talk about positive duty.

Contents

1. Introduction 2. Cosmopolitans, anti-cosmopolitans and the question of global distribution: where does ganshi fit in ? 3. Western moral cosmopolitanism and right-based approach to global poverty: a noble lier or hollow promise 4. Duty-bearer approach to alleviate global poverty: western moral cosmopolitans and Gandhi 5. Gandhi's compassionate cosmopolitanism and global poverty. Conclusion. Bibliography

12. सतीश कुमार

दक्षिण एशिया मे नाभिकीयकरन तथा क्षेत्रीय सुरक्षा एवं स्वथयित्व पर इसका प्रभाव।

निर्देशिका: डा. बिपिन कुमार तिवारी

Th 27148

सारांश

इस अध्ययन का मुख्य उधेश्य दक्षिण एशिया में परंपरागत नभकीय निवारक सिद्धांत की जाच करना है नभकीय निवारक सिद्धांत का मानना है की परमाणु धारक राज्यों के मध्य युद्ध नहीं होते अर्थात नाभकीय हथियारों के द्वारा दो देशों के मध्य युद्धों को रोका जा सकता है विश्व में जीतने देश के पास परमाणु हथियार होगेन विश्व में उतनी अधिक शांति की स्थापना होगी क्योंकि परमाणु हथियार की प्रकृति विध्वंशंकारी होती है इनके प्रयोग से विनाश सुनिश्चित होता है इस भय के कारण एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करते। इस सिद्धांत की जड़े रूस-अमेरिका सम्बन्धों में देखि जा सकती हैं जहां शीत युद्ध के दौरान कई बार युद्ध की स्थिति बनी लेकिन दोनों महाशक्तियों के मध्य युद्ध नहीं हुआ। भारत एवं पाकिस्तान के द्वारा परमाणु परीक्षण से 23 वर्षों तक दोनों देशों के मध्य कई परंपरागत एवं पूर्ण युद्ध (full fleddge)नहीं हुआ लेकिन युद्ध के हालत कई बार बन चुके हैं। कारगिल संघर्ष , भारत –पाक सैन्य गरिरोध (2001-02) बुम्बई आतंकी हमला (2008),उरी आतंकी हमला (2016)पुलवामा आतंकी हमला (2019) इत्यादि संकटों के दौरान भारत व पाकिस्तान के प्रमप्रगत व पूर्ण युद्ध का मार्ग नहीं चुना गया इस सभी सैन्य गतिरोध के बाबजूद दोनों देशों के मध्य युद्ध नहीं हुआ

विषय सूची

1. प्रस्तावना 2. नाभिकीय शस्त्रीकरण का सैद्धांतिक विश्लेषण 3. भारत एवं पाकिस्तान के नाभिकीय हथियारों का विकास (1947-1998) 4. भारत और पाकिस्तान द्वारा 1998 के परमाणु परीक्षण के कारण 5. नाभिकीय हथियारों का स्वथयित्व मे योगदान 6. सार एवं निष्कर्ष. संदर्भ ग्रंथ सूची।

13. शर्मा (गरिमा)

लोकतान्त्रिक राजनीति मे अल्पसंख्यक: भारत मे मुस्लिम एवं इजराइल मे अरब का एक तुलनात्मक आध्ययन।

निर्देशिका: आचार्य सुनील कुमार चौधरी

Th 27147

सारांश

इस स्मपूर्ण शोघ प्रबंध को सामुदायिक उपागम के दृष्टिकोण से अध्ययन करने का प्रयास किया गया है सामुदायिक उपागम से समस्या को अवलोकन करते समय सदैव इसे उदरवादी विचार धारा के विपरीत प्रस्तुत किया गया है प्रशतुत शोध के अंतर्गत सामुदायिक उपागम को व्यक्तिगत अधिकारों के विपरीत न होकर दोनों के माध्य समंजस्य स्थापित करने के दृष्टिकोण से प्रयोग किया गया है राजनीतिक गतिविधि में जहां प्रतेक व्यक्ति की महत्ता होती है उस ही प्रकार प्रतेक व्यक्ति का मत उसके समुदाई से भी प्रभावित होता है इस कारण ही चुनावी राजनीति के अंतर्गत शंखया एवं शक्ति का गठजोड़ अधिक बढ़ जाता है इस शंखया एवं शक्ति का अल्पसंख्यक समुदाय के राजनीतिक व्यवहार पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है इस प्रभाव का अध्ययन करने के लिए इस अध्ययन को सामुदायिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने का प्रयास किया गया है भारत और इज़राइल दोनों देशो के तुलनात्मक अध्यन में अनेक सांस्कृतिक एटिहासिक एवं राजनीतिक सम्बन्धों को पाया जा सकता है

विषय सूची

1. आमुख 2. शोध प्रणाली 3. अल्पसंख्यक एवं अल्पसंख्यकवाद: परीपेक्ष्य 4. भारत एवं इजराइल की लोकतान्त्रिक राजनीति मुस्लिम एवं अरब की अवस्थिति 5. लांबंदीकरण एवं एकीकरण : राजनीतिक एवं सामुदायिक अभिजात वर्ग की भूमिका 6. मुस्लिम एवं सामुदायिक की राजनीतिक अभिमुखता 7. परिवर्तित राजनीति मे अल्पसंख्यक: चुनौतियाँएवं अवसर .निष्कर्षतामक अवलोकन .प्राथमिक स्रोत संदर्भ सूची ।

14. SHUKLA (Shipra)

Feminist Readings of Secession: Exploring Alternate Trajectories.

Supervisor: Prof. Navnita Chadha Behera

Th 26874

Abstract

Thesis Feminist Readings of Secession: Exploring Alternate Trajectories Abstract Secession, as a political phenomenon, is generally viewed as a disruptive challenge to the fixed territorial borders in the contemporary international system. This thesis is located in the normative philosophical debates on the fundamental question of whether social groups, communities and nationalities have a right to secede. It offers a detailed overview of the main theories of secession categorized into three primary groups that are the nationalist theories, liberal-democratic theories and the 'remedial right only' theory. This is followed by a gender critique of these theories of secession. Given the gendered nature of these theories, the thesis aims to address the gaps in theorizing secession from a feminist perspective within the broader context of the normative political philosophy. In doing so, it seeks to contribute to developing a more comprehensive understanding of secession from a feminist standpoint. Through a critical examination of core elements involved in secessionist demands and processes including that of the role of identity, culture, and gendered violence perpetuated by the state as well as the groups seeking secession, this research highlights the limitations of secessionist projects and their reproduction of patriarchal state structures and the inability of fixed territories for accommodating diverse identities and intersectional privileges and burdens. It challenges the fixed territorial framework for providing political representation to diverse social groups and calls for re-examining the very purpose of secession to explore if the oft-stated

political goals of protection of culture, autonomy, and more democratic representation of groups seeking secession can be achieved without necessitating territorial separation. The thesis concludes with a discussion on the challenges in developing a feminist notion of secession.

Contents

1. Introduction 2. Theorizing secession: a contested domain 3. Nationalist theories of secession & a feminist critique 4. Liberal- democratic theories of secession & a feminist critique 5. Remedial right only theory of secession & a frminist critique 6. Feminist engagements with theorizing secession. Conclusion. Bibliography.

15. स्निहल (पंकज कान्त)
बहुभाषिकता और ज्ञान की राजनीति विशविदयालयी परिवेश मे भाषा ज्ञान और राजनीति के अंतरसम्बन्धों का अध्ययन।
निर्देशिका: प्रो. मधुलिका बनर्जी
Th 26875

सारांश

Aadhaar project of India is the biggest national biometric Identification system of the world. From 2016 onwards, Aadhaar is mandatory to avail benefits of welfare large scale

विषय सूची

1. भाषा ज्ञान और राजनीती की अंतर – अनुशासनात्मकता 2. यूरोपीय ज्ञानदोय उपनिवेशवाद और राष्ट्रवादी संभावनाओं के बीच भाषा विमर्श 3. विशविदयालयी परिवेश मे भाषायी नियोजन एवं व्यवहार 4. विशविदयालयी परिवेश मे अवसरों का संकुचन, असमानता का पुनरउत्पादन और संग्यानात्मक संभावनाएं 5.पुस्तक संदर्भ सूची ।

16. सुमन
भारत टेलीविज़न विज्ञापन मे नारी का चित्रण: मुक्ति और दमन।
निर्देशिका: डा. विजयलक्ष्मी नन्दा
Th 27149

सारांश

मेरे शोध "भारतीय टेलिलिज़न लिज्ञापन मं नारी का लित्रण: मुलि और दमन" का मुख्य ईद्देश्य भारतीय टेलिलिज़न लिज्ञापनं मं प्रिाररत और प्रसाररत की जाने वाली स्त्री की छलि/लित्रण के अधार पर टेलिलिज़न लिज्ञापनं मं स्त्री की मुलि और दमन जैसे प्रश्नों का ऄध्ययन करना है साथ ही लिज्ञापनं मं मलहिाओं की प्रिलित छलि और स्त्री की सामालजक छलि के बीच सम्बंध का ऄध्ययन करते हुए, इसके प्रभावो को समझना है। चूंकि किसी भी संस्था, समाज और लिए विचारधारा मं स्त्री-पुरुष के मध्य सम्बंध लनलित रूप से ऄपने पूर्वग्रहं से प्रभालित रहते हं और राजनीलत, समाज, सांस्कृलतक गलतलिलध और मीलडया मं स्त्री की प्रिलित छलि के पीछे आलतहास मं लभन्न लभन्न समयं पर लनर्ममत की गइ ईसकी छलि बहुत हद तक ईत्तरदायी है वर्ततामान मीलडया मं स्त्री की प्रचलित छवि का ऄध्ययन करने व उसे समझने के लिए प्राचीन और औपलनिेलशक पृष्ठभूलम को समझने की कोलशश कक गइ है और आसे 1990 के दशक के वैशवीकरण और ईदारीकरण की पृष्ठभूलम पर अधाररत ककया गया है। क्ययंकक 1990 के दशक मं वैशवीकरण की पूँजीवादी प्रकिया ने मीलडया तकनीक, सामालजक मूल्य, लित्रण और लिंग सम्बन्ध ज्ञान, सत्य, भाषा और सांस्कृलतक सीमा को प्रभालित करने के साथ आसमं पररितान भी ककया है। यह शोध मलहिाओं पर टेलिलिज़न लिज्ञापनं के वास्तलिक और अदशा प्रभावॉन की वास्तलिकता को समझने का प्रयास है। क्ययंकक मलहिाओं के संदभा मं प्रायः टेलिलिज़न लिज्ञापनं को जंडर सम्बन्धं मं न्याय, स्ितंत्रता और समानता स्थालपत करने से जोड़ा जाता है। प्रथम ऄध्याय मं नारी के ऄिग-ऄिग सिद्धांतं का ऄध्ययन करते हुए समाज मं मलहिाओं की लस्थलत पर ईनके विचारकों को शालमि ककया गया गया है। जिसमे

उदार नारिवाद रेलडकिल नारीवाद और समाजिादी नारीवादी विचार प्रमुख हं। आसके साथ ही मीलडया माध्यमं और ईसमं मलहिाओं के लित्रण पर आन नारीवादी लसद्धांतं के विचार और प्रस्तालित समाधान को भी शालमि ककया गया है। आसके ऄलतररि विचारक माथाा नुस्सबौम के क्षमता लसद्धांत के तहत लिज्ञापनं मं मलहिाओं के लित्रण का लिश्लेषण ककया गया है।

विषय सूची

1. प्रस्तावना 2. महिलाएँ व मीडिया : मीडिया का नारिवाद दृष्टिकोण 3. पूर्व औपनिवेशिक काल : ऋग्वेदिक उत्तेर्वेदिक और मध्यकाल मे महिलाओं की स्थिति 4. औपनिवेशिक काल : मीडिया और महिलाओं का चित्रण 5. उत्तर औपनिवेशिक व पूर्व वैश्वीकृत : मीडिया माध्यमों मे महिलाओं का चित्रण 6. कंटेन्ट एनालिसिस और डेटा विश्लेषण 7. भारतीय टेलिविजन विज्ञापनों मे महिलाओं का चित्रण निष्कर्ष .संदर्भ -ग्रंथ सूची ।